



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 10, 2000/आश्विन 18, 1922

No. 136]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2000/ASVINA 18, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2000

सं. टीएएमपी/65/2000-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार कंडला पत्तन न्यास द्वारा निर्यात कार्गो पर मांगे गए विलंब शुल्क प्रभारों के संबंध में मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं० टीएएमपी/65/2000-केपीटी

मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड

.....

आवेदक

बनाम

कंडला पत्तन न्यास (केपीटी)

.....

गैर-आवेदक

आदेश

(सितम्बर, 2000 के 26वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला कंडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा विलंब शुल्क की अनुचित और अनधिकृत मांग के विरुद्ध मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन से संबंधित है।

2.1 आवेदक द्वारा उल्लिखित के अनुसार मामले के तथ्य संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :-

- (i) मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड बाणिज्य मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त एक 'स्टार ट्रेडिंग हाऊस' है, जो कि अनेक वर्षों से केपीटी से मुख्यतया कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है।

- (ii) कथित निर्यात कार्गो के पोतलदान में विलंब हो गया था और मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड के नियंत्रण से बाहर के कारणों से 4 अप्रैल, 1998 से 30 मई, 1998 की अवधि के लिए विलंब शुल्क लगाया गया था, जिसका कंपीटी को उनके परिकलन के अनुसार भुगतान कर दिया गया था ।
- (iii) 9 जून, 1998 को चक्रवात के कारण, कंपीटी के निर्देशों के अनुसार खराब हुए कार्गो को नष्ट करने के बाद उक्त निर्यात कार्गो को पत्तन मोदाम से हटा दिया गया था ।
- (iv) उक्त निर्यात कार्गो अंततः 9 सितम्बर, 1998 को निर्यात कर दिया गया था ।
- (v) कंपीटी ने 18 जून, 2000 से विलंब शुल्क के रूप में 43,37,600/-रुपए और विलंब से किए गए भुगतान पर ब्याज के रूप में भुगतान किए जाने की मांग की है ।
- (vi) कंपीटी ने उक्त कार्गो पर 10 दिन के भीतर विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए अपने दिनांक 5 जुलाई, 2000 के पत्र द्वारा मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी ।

2.2. मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड ने कंपीटी द्वारा विलंब शुल्क प्रभार लगाए जाने के विरुद्ध अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत की है :-

- (i) जल भूतल परिवहन मंत्रालय से 30 जून, 1999 के पत्र की प्रति, जिसमें निम्नलिखित कारणों से मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड को निर्यात पर छूट देने के लिए कंपीटी को निर्देश दिया जाए :-
 - (क) कार्गो का वास्तव में निर्यात किया गया था ।
 - (ख) यह अकल्पनीय है कि कोई निर्यातक कार्गो को पत्तन में रखे और उसके लिए विलंब शुल्क का भुगतान करे । निर्यात समय पर नहीं हो सका, क्योंकि कारण निर्यातक के नियंत्रण से बाहर थे ।
 - (ग) पत्तन क्षेत्र से कार्गो निकालने पर भी व्यय होता है । केवल किसी चरम स्थिति में कार्गो को क्षति होती है और उसे बाहर निकाला जाता है ।
- (ii) ओरिएन्टल इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड से दिनांक 17 जून, 2000 के पत्र की प्रति, जिसके अनुसार न तो मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कोई बीमा दावा किया गया है अथवा न ही उक्त निर्यात कार्गो पर उनके द्वारा कोई भुगतान किया गया है ।
- (iii) डॉक दरों के मान की प्रति जिसमें विलंब शुल्क प्रभारों की तालिका के नीचे मद संख्या 6 की टिप्पणी संख्या 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :-

“पोतलदान के लिए निश्चित प्रयास किए बिना माल अंदर लाने और हटाने पर कोई निःशुल्क दिवस अनुमत्य नहीं होंगे ।”

2.3. मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड ने तर्क दिया है कि कंपीटी निम्नलिखित के मददेनजर महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 52 के प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है :-

- (i) कंपीटी के न्यासी बोर्ड ने 9 जनवरी, 97 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प संख्या 71 द्वारा दरों के मान और शर्तों के विवरण में इस तर्क के आधार पर कुछ परिवर्तन किए थे कि ये मात्र व्याख्याएं हैं और संशोधन नहीं हैं ।
- (ii) किए गए परिवर्तनों में से एक निम्नलिखित था :-

“विलंब शुल्क दर में 50 प्रतिशत की छूट वास्तव में केवल निर्यात किए गए कार्गो पर अनुमत्य होगी, परंतु अन्यथा नहीं ।”

- (iii) उपर्युक्त परिवर्तन से विलंब शुल्क प्रमारों में 100 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, जोकि हर प्रकार से दरों के मान और शर्तों के विवरण में परिवर्तन है, जिसके लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1983 की धारा 52 के अधीन महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का अनुमोदन और राजपत्र में अधिसूचित किया जाना अपेक्षित होता है ।

3. मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड ने अपने दिनांक 9 अगस्त, 2000 के पत्र द्वारा उल्लिखित तथ्यों के आधार पर उनके मामले की समीक्षा करने और उनकी पात्रता तथा नियमों एवं विनियमों के अनुसार लाभ देने के लिए अध्यक्ष (केपीटी) से पुनः अनुरोध किया है ।

4. अम्यावेदन की एक प्रति केपीटी को टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी । केपीटी की टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है :-

- (i) बोर्ड ने पोतलदान न किए गए निर्यात कार्गो पर विलंब शुल्क माफ करने के लिए मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड के अम्यावेदन को रद्द कर दिया था, क्योंकि संबंधित पोतवणिक द्वारा पोतलदान न किए जाने के लिए केपीटी किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं था ।
- (ii) मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड की ओर से मैसर्स लीलाधर पासू फारवर्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित मुद्दों पर गुजरात उच्च न्यायालय (अहमदाबाद) में विशेष सिविल आवेदन पत्र दाखिल किया था :-
 - (क) 15 दिन की निःशुल्क अवधि प्रदान न करना; और
 - (ख) निर्यात कार्गो के लिए विलंब शुल्क प्रमारों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान न करना ।
- (iii) गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 17 जुलाई, 2000 के आदेश द्वारा पत्तन द्वारा तैयार बिलों को रद्द कर दिया और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1983 की धारा 56 के अंतर्गत केपीटी को नोटिस जारी करने की छूट तथा तत्पश्चात याचिकाकर्ता को अपनी बात कहने का अवसर देने और कानून के अनुसार मामले को निपटाने के लिए उन्हें अलग कर दिया ।
- (iv) गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 43,47,760/-रुपए की राशि के विलंब शुल्क प्रमारों के अंतर की मांग करते हुए मैसर्स लीलाधर पासू फारवर्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को एमपीटी अधिनियम, 1983 की धारा 56 के अंतर्गत 4 अगस्त, 2000 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । कारण बताओ नोटिस पर मैसर्स लीलाधर पासू फारवर्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुछ आपत्तियां उठाई गई थीं, जोकि जांचाधीन हैं ।
- (v) मामले की उच्च न्यायालय में पहले से ही चल रही कार्यवाही के मददेनजर टीएएमपी मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड को व्यक्तिगत सुनवाई में भाग न लेने के लिए परामर्श दे सकता है, ताकि किसी प्रकार की कानूनी अड़चनों से बचा जा सके ।

5.1 केपीटी से प्राप्त टिप्पणियों की एक प्रति मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड को आगे टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी ।

5.2 मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड ने अपने दिनांक 13 सितम्बर, 2000 के पत्र द्वारा अपनी पूर्ववर्ती टिप्पणियों को दोहराया है । उन्होंने आगे निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं :-

- (i) उन्होंने विलंब शुल्क प्रमारों को माफ करने के लिए केपीटी से अनेक बार संपर्क किया है ।
- (ii) केपीटी ने जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों को भी रद्द कर दिया है ।
- (iii) चूंकि, केपीटी ने इसकी सेवाएं बंद कर देने की धमकी दी थी, इसलिए उनके पास गुजरात उच्च न्यायालय में मामला दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था ।
- (iv) उनका दृढ़ विश्वास है कि टीएएमपी के हस्तक्षेप से इस मामले का हमेशा के लिए समाधान करने में सहायता मिलेगी ।

6.1. इस मामले में एक संयुक्त सुनवाई 16 सितम्बर, 2000 को कंडला में आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :—

मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड

- (i) उन्होंने उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था और न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। मामला बंद हो गया है और प्राधिकरण द्वारा इस मामले पर विचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है।
- (ii) वे प्रभावित पक्ष हैं और इसलिए उन्होंने टीएएमपी से संपर्क करने को चुना है। उच्च न्यायालय का आदेश उन्हें राहत देने के लिए है।
- (iii) उन्हें टीएएमपी के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। अन्यथा वे उच्च न्यायालय का सहारा नहीं लेते।
- (iv) उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि प्राधिकरण उनके मामले पर विचार करता है तो वे उच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी ओर से कार्रवाई नहीं करेंगे।

कंडला पत्तन न्यास (केपीटी)

- (i) उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में केपीटी मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है।
- (ii) उच्च न्यायालय ने पत्तन को नए सिरे से निर्णय करने का अधिकार दिया है, जिसे टीएएमपी द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता।
- (iii) जब तक मामला निपट नहीं जाता, तब तक सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी।

6.2 संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित निर्णय किए गए :—

- (i) केपीटी एक विशेष वादकालीन आपत्ति दाखिल करेगा।
- (ii) प्राधिकरण, केपीटी द्वारा उठाई गई इस प्रकार की प्रारंभिक आपत्ति पर औपचारिक आदेश पारित करेगा।
- (iii) आवेदक यह स्पष्ट करते हुए एक पत्र प्रस्तुत करेगा कि उन्होंने प्राधिकरण से पहले संपर्क क्यों नहीं किया और यह भी उल्लेख किया जाएगा कि वे केपीटी के समक्ष लंबित अन्य मामले पर कार्रवाई नहीं करेंगे।

7. मैसर्स अमीरा फूड्स (इंडिया) लिमिटेड ने अपने दिनांक 18 सितम्बर, 2000 के पत्र द्वारा संयुक्त सुनवाई में किए गए अनुरोध की पुष्टि की थी कि वे इस प्राधिकरण के बारे में पहले नहीं जानते थे, इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय से संपर्क किया। उन्होंने अपने दिनांक 19 सितम्बर, 2000 के पत्र द्वारा उल्लेख किया है कि केपीटी के पास लंबित मामला केवल व्यक्तिगत सुनवाई का है, जैसाकि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है और वे इसे त्याग देने के लिए तैयार हैं और इस मामले में निर्णय के लिए वे इसे प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत कर देंगे।

8. इस मामले की जांच-पड़ताल के दौरान एकत्र समग्र सूचना और प्राधिकरण के समक्ष इन कार्यवाहियों को चलाए जाने के बारे में केपीटी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों के संदर्भ में तथा समग्र ध्यान दिए जाने के आधार पर निम्नलिखित स्थिति उभरती है :—

- (i) इस संदर्भ में केपीटी को संयुक्त सुनवाई में एक विशेष वादकालीन आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करनी थी, जिस पर यह प्राधिकरण औपचारिक आदेश पारित कर सकता था। केपीटी ऐसा तत्काल करने के लिए सहमत था, ताकि यह प्राधिकरण की 26 सितम्बर, 2000 को होने वाली बैठक में विचारार्थ लिया जा सके। केपीटी ने ऐसी कोई भी लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। फिर भी, इस प्राधिकरण ने संयुक्त सुनवाई में उनके अनुरोधों और 9 सितम्बर, 2000 के (पूर्ववर्ती) पत्र के संदर्भ में इस मामले पर विचार किया है।

- (ii) ऐसा नहीं लगता कि आवेदक फर्म कानूनी प्रक्रिया के साथ कोई लुका-छिपी कर रहा है, जैसाकि केपीटी ने आरोप लगाया है कि यह फर्म समाधान के लिए कभी एक कानूनी मंच से संपर्क कर रही है तो कभी दूसरे मंच से और न्याय प्रक्रिया को कारगर रूप से रोक रही है। उनका यह स्पष्टीकरण कि उन्हें टीएएमपी की कोई जानकारी नहीं थी, पूर्णतया संतोषजनक है। वस्तुतः, न्यायालय से कोई समाधान पाना अधिक खर्चीला है और समय भी अधिक लगता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई वादी ऐसा क्यों करेगा, जबकि एक सस्ता और त्वरित उपाय उपलब्ध है। केपीटी ने यह नहीं दर्शाया है कि ऐसा करने के पीछे आवेदक फर्म का कोई विशेष कारण है।
- (iii) केपीटी का यह आरोप कि इस प्राधिकरण द्वारा चलाई गई कार्यवाहियां उच्च न्यायालय के आदेश के कारण आरंभ हुई कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप है, स्वीकार्य नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित कर दिया है और मामला बंद कर दिया है। दूसरे शब्दों में, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और न ही उसने किसी कार्यवाही का निर्देश दिया है।
- (iv) माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदक फर्म एक पीड़ित पार्टी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले पर निर्णय उनके पक्ष में दिया है। फिर भी (अनुकूल) निर्णय के बावजूद, इस प्राधिकरण जैसे एक मंच के अस्तित्व की जानकारी होने पर, उन्होंने हमसे राहत के लिए संपर्क किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस कार्रवाई से केपीटी अपने को पीड़ित क्यों अनुभव कर रहा है।
- (v) यहां यह जानना भी उचित है कि संयुक्त सुनवाई (और बाद में इसकी लिखित पत्र द्वारा पुष्टि) में आवेदक फर्म ने आश्वासन दिया था कि इस प्राधिकरण द्वारा उनकी याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिये जाने की स्थिति में वे उनके पक्ष में उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई का त्याग कर देंगे।
- (vi) उच्च न्यायालय के संदर्भगत आदेश में किसी विशेष कार्रवाई के बारे में न तो कोई निर्देश दिया है और न ही इसने केपीटी को कोई विशेष राहत दी है। इसे देखते हुए, इस मामले के गुणावगुणों के आधार पर इस पर इस प्राधिकरण द्वारा विचार कए जाने पर उच्च न्यायालय के उक्त आदेश द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है।
- (vii) कानूनी दृष्टि से इस प्राधिकरण के समक्ष ऐसी कार्यवाहियां बनाए रखने के संबंध में उठाए गए मुद्दों के बावजूद तथ्यात्मक महत्व के एक मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह मुद्दा वाद के कारण से संबंधित है। इस मामले में आवेदक फर्म की आपत्ति केपीटी द्वारा प्रस्तुत बिलों से संबंधित है। इन बिलों को माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। दूसरे शब्दों में, अब स्थिति यह है कि कोई 'बिल' मौजूद नहीं है, जिस पर आवेदक-फर्म आपत्ति कर सके।

वस्तुतः, उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत केपीटी ने महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 58 के अधीन नए सिरे से कार्यवाही आरंभ की है। अब जो बात मौजूद है, वह यह है कि एक नोटिस है, जिसमें अदा की जाने वाली राशि का उल्लेख है। पार्टी की सुनवाई के बाद बोर्ड के न्यासियों को देय राशि का 'निर्धारण' करना था। तब वह बिल की राशि कही जा सकती थी, जिसका संबंधित पार्टी से दावा किया जाना था। इसलिए, अब आवेदक फर्म केपीटी को किसी राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है और केपीटी इस पर आपत्ति करने का दावा नहीं कर सकता।

- (viii) संभवतः इस मामले के इस पहलू के संदर्भ में ही केपीटी ने यह आरोप लगाया है कि इस प्राधिकरण के समक्ष कोई भी कार्यवाही चलाने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दिया गया अधिकार समाप्त हो जाएगा। यद्यपि, केपीटी का यह विचार कानूनी तौर पर उचित नहीं है, जैसा कि इस पैराग्राफ में पहले विश्लेषण किया गया है, वाद का कारण न होने से संबंधित उल्लिखित वास्तविक स्थिति के मद्देनजर यह प्राधिकरण इस मामले को इस चरण में स्वीकार नहीं करना चाहता।
- (ix) आवेदक फर्म ने इस मामले में तत्काल समाधान का अनुरोध करते हुए उल्लेख किया है कि देयताओं का तत्काल भुगतान न होने पर केपीटी ने सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। अब यह स्थिति समाप्त हो चुकी है। उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर केपीटी ने आश्वासन दिया है कि जब तक मामला निपट नहीं जाता, तब तक सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी।
- (x) गुजरात उच्च न्यायालय का संदर्भगत आदेश 17 जुलाई, 2000 को पारित किया गया था। आवेदक फर्म ने आवेदन पत्र इस प्राधिकरण को 24 जुलाई, 2000 को भेजा था। उनकी गलती यह रही है कि उन्होंने अपने आवेदन-पत्र में उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख नहीं किया था। यदि, उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें उसी चरण में यह परामर्श दे दिया जाता कि वाद का कारण होने पर वे इस प्राधिकरण से संपर्क स्थापित कर सकते थे।

9. परिणामतः, और ऊपर दिए गए कारणों से यह प्राधिकरण एतद्वारा इस चरण में इन कार्यवाहियों को आगे स्वीकार न करने का निर्णय करता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/143/2000/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2000

No. TAMP/65/2000-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation made by M/s. Amira Foods (India) Limited about demurrage charges on export cargo demanded by the Kandla Port Trust, as in the Order appended hereto.

SCHEDULE**Case No. TAMP/65/2000-KPT**

M/s. Amira Foods (India) Ltd. ... **Applicant**

Vs.

The Kandla Port Trust ... **Non Applicant**

ORDER

(Passed on this 26th day of September 2000)

This case relates to a representation made by M/s. Amira Foods (India) Limited against the unjustified and illegal demand of demurrage by the Kandla Port Trust (KPT).

2.1. The facts of the case in brief, as mentioned by the Applicant, are as given below:

- (i). M/s. Amira Foods (India) Limited is a "Star Trading House" recognised by the Ministry of Commerce and exporting mainly the agro products from the KPT since many years.
- (ii). The shipment of the export cargo in question was delayed and had incurred demurrage for the period from 4 April 1998 to 30 May 1998 due to the reasons beyond the control of M/s. Amira Foods (India) Limited, which were paid to the KPT as per their calculations.
- (iii). Due to cyclone on 9 June 1998, the said export cargo was removed from the port godown after destroying the damaged cargo as per the directions of the KPT
- (iv). The said export cargo was finally exported on 9 September 1998.
- (v). The KPT has demanded a payment of Rs.43,37,600/- towards demurrage from 18 June 2000 and also interest on delayed payment.
- (vi). The KPT has served a notice vide their letter dated 5 July 2000 to M/s. Amira Foods (India) Limited to pay the demurrage on the said cargo within 10 days failing which their services will be stopped.

2.2. M/s. Amira Food (India) Limited have furnished the following documents information in support of their contention against the levy of demurrage charges by KPT:

- (i). A copy of the letter dated 30 June 99 from the Ministry of Surface Transport issuing a directive to the KPT, that export rebate should be made available to M/s. Amira Foods (India) Limited due to the following reasons:
 - (a). The cargo was actually exported.

- (b). It is inconceivable that an exporter would keep cargo in the port and pay demurrage for it. The export did not take place in time only because the reasons were beyond the control of the exporter.
- (c). Taking out cargo from the port area also involves expenses. It is only in extreme situation that the cargo was damaged, it had been taken out
- (ii). A copy of the letter dated 17 June 2000 from the Oriental Insurance Company Limited that no Insurance claim was either made by M/s. Amira Foods (India) Limited or paid by them on the said export cargo.
- (iii). A copy of the dock Scale of Rates, Note No. 3 of item 6 under the demurrage charges table, which states as follows:

" No free days shall be allowed on goods brought in and removed without a definite attempt having been made for the shipment.

2.3. M/s. Amira Foods (India) Limited have argued that the KPT is violating the provision of Section 52 of the Major Port Trust Act 1963 in view of the following:

- (i). The Board of Trustees of KPT, vide Resolution No.71, in their meeting held on 9 January 97 made certain changes in the Scale of Rates and in the statement of conditions taking the plea that these are mere interpretations and not amendments.
- (ii). One of the changes made was as follows:

"50% rebate in demurrage rate shall be allowed only on cargoes physically exported but not otherwise."
- (iii). The above change will increase the demurrage charges by 100% which is by all means a change in the Scale of Rates and statement of conditions, which requires approval of the Tariff Authority and Notification in the Gazette under section 52 of the Major Port Trust Act, 1963.

3. M/s. Amira Foods (India) Limited vide their letter dated 9 August 2000, have once again requested the Chairman (KPT) to review their case on the facts stated and extend the benefit as per their entitlement and rules and regulations.

4. A copy of the representation was sent to the KPT for comments. The comments of the KPT are summarised below:

- (i). The Board rejected the representation made by M/s. Amira Foods (India) Limited for waiver of demurrage on export cargo not shipped as the KPT was in no way responsible for non-effecting of the shipment by the shipper concerned.
- (ii). M/s. Liladhar Pasoo Forwarders Private Limited on behalf of M/s. Amira Foods (India) Limited filed a special civil application in the High Court of Gujarat (Ahmedabad) for,
 - (a) not allowing 15 days free period; and,
 - (b) non granting of 50% rebate in demurrage charges for export cargo.
- (iii). The Gujarat High Court vide its order dated 17 July 2000 quashed the bills raised by the Port and set them aside with a liberty to the KPT to issue a notice under Section 56 of the MPT Act, 1963, and, thereafter, give an opportunity of being heard to the petitioner and decide the matter in accordance with law.

- (iv). In compliance with the order of the High Court of Gujarat, a show cause notice was served on 4 August 2000, under Section 56 of the MPT Act, 1963 to M/s. Liladhar Pasoo Forwarders Private Limited demanding a difference of demurrage charges amounting to Rs.43,37,760/-. Certain objections were raised by M/s. Liladhar Pasoo Forwarders Private Limited on the show cause notice which are under examination.
- (v). In view of the matter already proceeding in the High Court, the TAMP may advise M/s. Amira Foods (India) Limited not to attend the personal hearing so as to avoid legal complications of any nature.

5.1. A copy of the comments received from the KPT was forwarded to M/s. Amira Foods India Limited for further comments.

5.2. M/s. Amira Foods (India) Limited, vide their letter dated 13 September 2000 have reiterated their earlier comments. They have made the following further comments:

- (i). They have approached the KPT several times for waiver demurrage charges.
- (ii). The KPT has also turned down the directions given by the MOST.
- (iii). They were left with no option but to file a case in the Gujarat High Court since the KPT threatened to stop its services.
- (iv). They firmly believe intervention of the TAMP will help in resolving the matter once for all.

7.1. A joint hearing in this case was held on 16 September 2000 at Kandla. During the joint hearing, the following submissions were made:

M/s. Amira Foods (India) Limited

- (i). They filed a case in the High Court and the order has been passed by the court. The case is closed and there is no bar to the Authority to consider the case.
- (ii). They are the affected party and they have chosen to go to TAMP. The High Court order is for providing relief to them.
- (iii). They were not aware of the TAMP earlier. Otherwise they would not have gone to the High Court.
- (iv). They assured that they would forgo action on the High Court order on their part if the Authority considers their case.

Kandla Port Trust (KPT)

- (i). Pursuant to the Order of the High Court, the case is being processed by the KPT.
- (ii). The High Court has given the Port, a right to decide afresh which cannot be extinguished by TAMP.
- (iii). There will be no disruption in services until the cases disposed of.

7.2. The following decisions were taken in the joint hearing:

- (i). The KPT will file a specific Interlocutory objection.
- (ii). The Authority will pass a formal order on the preliminary objection so raised by the KPT.
- (iii). The applicant is required to furnish a letter explaining why they did not approach the Authority earlier as also stating that they will not be pursuing the other case pending before the KPT.

8. M/s. Amira Foods (India) Limited vide their letter dated 18 September 2000 confirmed their submission made during the joint hearing that they were not aware of this Authority earlier and hence they had approached the High Court. They have also stated vide their letter dated 19 September 2000 that the only matter pending with the KPT is the personal hearing as directed by the High Court and they are ready to forgo it and submit to the jurisdiction of the Authority to decide the matter.

9. With reference to the totality of information collected during the processing of this case and the preliminary objections raised by the KPT about maintainability of these proceedings before the Authority, and based on a collective application of mind the following position emerges:

- (i). The KPT was required at the joint hearing to file a specific interlocutory objection in writing with reference to which this Authority could pass a formal order. The KPT had agreed to do so immediately so that this case could be taken up for consideration in the Authority's meeting on 26 September 2000. The KPT has not filed any such written objection. Nevertheless, this Authority proceeds with consideration of this case with reference to their pleadings at the joint hearing as also their (earlier) communication dated 9 September 2000.
- (ii). The Applicant-Firm does not appear to be playing ducks and drakes with the legal process, as alleged by the KPT, by approaching one legal forum or another apparently for seeking redress but effectively stalling justice. Their explanation that they were not aware of the TAMP forum is quite convincing. Admittedly, seeking redress in a Court of Law is more expensive and more time-consuming. There is no reason why a litigant will opt for that when a cheaper and quicker remedy is available. The KPT has not also shown that there is any particular reason for the Applicant-Firm to do so.
- (iii). The KPT allegation that the proceedings entertained by this Authority amount to interference with the legal process initiated by the High Court order is not tenable. The fact of the matter is that the Hon'ble High Court has passed a final order and closed the case. In other words, there is no pendency of proceedings before the Hon'ble High Court or pursuit of process directed by it.
- (iv). In the case before the Hon'ble High Court, the Applicant-Firm was the aggrieved party. The Hon'ble High Court decided the case in their favour. Notwithstanding this (favourable) decision, upon getting to know about the existence of a forum like this Authority's, they have chosen to approach us for relief. It is not clear why the KPT feels aggrieved by this move.
- (v). It is relevant here to recognise that the Applicant-Firm has assured at the joint hearing (and, subsequently, followed it up with a written confirmation) that, in the event of their petition being entertained for consideration by this Authority, they will forgo action on the High Court order in their favour.
- (vi). The High Court order in reference has neither given a directive about any particular course of action nor has it given any special relief to the KPT. That

being so, there can be no hurdle arising from the said High Court order to this Authority's consideration of this case on its merits.

- (vii). Notwithstanding the points made about the maintainability of such proceedings before this Authority from a legal point of view, an issue of factual significance has nevertheless to be recognised. And, that is about the cause of action. In this case, the Applicant-Firm's objection is to the bills raised by the KPT. These bills have been quashed by the Hon'ble High Court. In other words, as of now, there is no 'bill' in existence which can be objected to by the Applicant-Firm.

It is a fact that, subsequent to the High Court order, the KPT initiated proceedings afresh under Section 56 of the Major Port Trusts Act. But, what is in existence now thereunder is only a 'notice' specifying an amount to be paid. After giving a hearing to the party, the Board of Trustees has to 'determine' the amount due. Only then can it be said to amount to a bill claiming the amount from the party concerned. As of now, therefore, the Applicant-Firm is not under obligation to pay any amount to the KPT; and, there is, therefore, no claim of the KPT for them to object to.

- (viii). Possibly, it is with reference to this aspect of the case that the KPT has alleged that any proceedings before this Authority will amount to extinguishing a right given to them by the Hon'ble High Court. Although this contention of the KPT is legally misconstrued, as analysed earlier in this paragraph, in view of the factual position described about the lack of cause of action, this Authority does not like to entertain this case at this stage.
- (ix). The Applicant-Firm had expressed an urgency for redress in this case citing a threat by the KPT to stop services failing immediate payment of dues. This situation does not exist anymore. The KPT has assured that, in view of the High Court order, there will be no disruption in services until the case is disposed of.
- (x). The order in reference of the Gujarat High Court was passed on 17 July 2000. The Applicant-Firm's application to this Authority was addressed on 24 July 2000. It is a mistake on their part not to have referred to the High Court order in their application. Had they done it, they could have been advised at that stage itself to approach this Authority only when there was a cause of action.

11. In the result, and for the reasons given above, this Authority hereby decides not to entertain these proceedings further at this stage.

S. SATHYAM, Chairman
[ADVT/III/IV/143/2000/Exty.]

